Liberalisation of rules for fixation of pension

394. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the rules for voluntary retirement from Government service at present;

(b) in what manner the pension of employees seeking voluntary retirement is fixed;

(c) what is present formula to fix the pension of Government employees on superannuation;

(d) whether Government propose to liberalise the existing criteria for fixation of pension on superannuation;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) The expression 'voluntary retirement' is generally used in cases where a Government servant seeks retirement after he has completed 20 years qualifying service. He has to give a notice of not less than three months in writing to the appointing authority. The notice of voluntary retirement requires acceptance by the appointing authority. However if the appointing authority does not refuse to grant the permission for voluntary retirement before the expiry of the period specified the retirement becomes effective from the date of expiry of the period of notice.

(b) The pension of an employee seeking voluntary retirement is worked out in the same manner as other cases of retirement except that in computing the amount of pension a weightage is allowed in the length of qualifying service upto a maximum of five years subject to the condition that the actual qualifying service plus the weightage does not exceed Thirty Three years and it does not take him beyond the date of superannuation.

(c) The pension is dependent on three factors—namely, the pension formula, average emoluments drawn during ten months preceding retirement and the length of qualifying service. Where the length of qualifying service is 33 years or more full pension equal to 50% of the average emoluments is allowed, where the length of qualifying service is more than 10 years but less than 33 years, the amount of pension is pro-rata less.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) The pension structure of Central Government pensioners was recently subjected to an in-depth examination by a high powered body, namely, the Fourth Central Pay Commission. The present criteria for fixation of pension on superannuation are based on the specific recommendations of the above-mentioned Commission which have been accepted by the Government.

भारत-पाक सीमा पर पाक सेना का जमाव

395. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाक सीमा पर पाक सेनाओं के जमाव से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या उचित कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपनी संक्रियात्मक तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय किए हैं । सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी

से नजर रखती है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। पूरी रक्षा तयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

गंगा नदी के जल को प्रदूषण रहित बनाये रखने के लिए किए गए प्रयास

396. **श्री राम जेटमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के जल को प्रदूषण रहित बनाये रखने हेतु पिछले कुछ वर्षों में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपायों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों से प्राप्त परिणामों की समीक्षा की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों के लिए 281.50 करोड़ रुपये की लागत पर 262 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। ये स्कीमें अवरोधन, दिशा-परिवर्तन, म्युनिसिपल अपशिष्ट जल के दिशा-परिवर्तन और उपचार, अल्प-लागत स्वच्छता; विद्युत शवदाहगृह की स्थापना एवं नदी तटाग्र की सुविधाओं के बारे में हैं। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण भी किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गंगा कार्य योजना पर 159.68 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) गंगा कार्य योजना की प्रगति एवं परिणामों की प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 147 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 47 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप अनुमानतः प्रतिदिन 329 मिलियन लीटर म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को अभी तक नदी में प्रवाहित होने से रोका जा सका है। उपर्युक्त के अलावा पांच सीवरेज उपचार संयंत्रों, 13 विद्युत शवदाहगृहों और 12 नदी तटाग्र सुविधाओं को भी पूरा किया जा चुका है। गंगा कार्य योजना में अल्प-लागत स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2727 सामुदायिक शौचालयों एवं 40529 निजी शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करना

397. **श्री राम जेटमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1990 के टाइम्स आफ इण्डिया में "इकोनोमिक पैनल अनहैप्पी विद जाब प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आर्थिक सलाहकार परिषद ने योजना आयोग द्वारा सुझाई गयी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने वाली नीति का समर्थन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए तैयार की गयी योजना की रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोबर्धन) : (क) जी, हां। सरकार को प्रश्न में उल्लिखित समाचार की जानकारी है।

(ख) आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा "1990 के दशक में विकास के लिए रोजगारोन्मुख कार्यनीति विकसित करने की दिशा में" शीर्षक अंतरिम रिपोर्ट में